संख्या- 06 /2021/212/74-2-2021-5(ब)/2020

प्रेषक,

अवध नारायण,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 28 अप्रैल, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय- रेशम निदेशालय" के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-02/सेरी0/लेखा/अधिष्ठान/बजट मांग/2021-22, दिनांक 05 अप्रैल, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय- रेशम निदेशालय" हेतु कुल प्राविधानित धनराशि रू0 2567.00 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ सरसठ लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 2567.00 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ सरसठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

मद सं0	मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त धनराशि
01	वेतन	1720.00	1720.00
02	मजदूरी	10.00	10.00
03	मंहगाई भत्ता	516.00	516.00
04	यात्रा व्यय	8.00	8.00
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	2.00
07	मानदेय	1.00	1.00
08	कार्यालय व्यय	8.50	8.50
09	विद्युत देय	45.00	45.00
10	जलकल/जल प्रभार	5.00	5.00
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5.00	5.00
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	5.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13	टेलीफोन पर व्यय	3.50	3.50
15	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	35.00	35.00
16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.00	2.00
17	किराया उपशुल्क और कर स्वामिस्व	5.00	5.00
19	विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	1.00	1.00
22	आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	1.00	1.00
29	अनुरक्षण	10.00	10.00
42	अन्य व्यय	6.00	6.00
43	सामग्री एवं सम्पूर्ति	20.00	20.00
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3.00	3.00
45	अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00	3.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	4.00	4.00
49	चिकित्सा व्यय	25.00	25.00
51	वर्दी व्यय	1.00	1.00
55	मकान किराया भत्ता	100.00	100.00
58	आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	20.00	20.00
	योग	**2567.00**	**2567.00**

(रूपए पच्चीस करोड सरसठ लाख मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत् राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किए जाने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे शासन को विलम्बतम 15 मार्च, 2022 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाय।

(5) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यों हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा है।

(6) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष 2021-22 में लक्षित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जाय।

(7) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत की गयी धनराशि के फेजिंग कार्य की प्रगति एवं अवसर के अनुसार किया जाय, जहाँ तक संभव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समान रूप से की जाय। वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में कुल स्वीकृत धनराशि के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि का व्यय न किया जाय।

(8) स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 में दी गयी शर्तों/नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता संबंधी शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का कडाई से पालन किया जाय, ताकि अपव्यय को रोका जा सकें। यात्रा व्यय, टेलीफोन व्यय, मोटर गाडियों का अनुरक्षण एवं ईंधन पर व्यय की मदों के अन्तर्गत होने वाले व्यय को इस प्रकार नियोजित किया जाय, जिससे यथा संभव आवंटित धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय को पूरा किया जा सकें और स्वीकृत धनराशि का व्यय समान रूप से प्रतिमाह सीमित रखते हुए पूरे वित्तीय वर्ष के लिये किया जाय।

(10) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(11) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की जा रही हैं। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा एवं पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(13) आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के लिये धनराशियाँ मानक मद 58 के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

(14) विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के बजट अलॉट्मेंट सिस्टम विषयक शासनादेश दिनांक 10-03-2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार रेशम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृति आदेश संख्या- 001-05बजट 2020 दिनांक 28/04/2021 द्वारा जारी की गयी है।

5- वित्त विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत कोविड-19 से संबंधित शासनादेशों मे दिये गए निर्देशों एवं प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

भवदीय,

अवध नारायण
संयुक्त सचिव।

संख्या- 06/2021/212/74-2-2021-5(ब)/2020 **तददिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, रेशम निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
(7) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।
(8) नियोजन अनुभाग-4
(9) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

अवध नारायण
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।